



छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला: 500 करोड़ का एआई मिशन समेत कई प्रस्ताव मंजूर, प्रदेश में BEML लगाएगी भारी मशीन बनाने का प्लांट

रायपुर। मंत्रिपरिषद ने 'छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मिशन' को मंजूरी दी है। इस मिशन का उद्देश्य राज्य में सुरासन, नई तकनीक, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। यह मिशन 5 वर्षों के लिए होगा, जिस पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस मिशन के तहत - 100 एआई डेटा लैब बनाई जाएंगी, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, 300 से अधिक एआई स्टार्टअप को सहायता दी जाएगी, 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को एआई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शासन के कार्यों को आसान और तेज बनाने के लिए 50 से अधिक एआई आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी। यह मिशन भारत सरकार के IndiaAI Mission के अनुरूप छत्तीसगढ़ को उत्तरदायी, नवाचार-आधारित और भविष्य उन्मुख डिजिटल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।



भारत सरकार का एक प्रतिष्ठित मिनीरल सार्वजनिक उपक्रम है। हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र हेतु यह राज्य का पहला उद्योग होगा, जिसकी स्थापना से छत्तीसगढ़ को देश के औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी और राज्य में आधुनिक भारी मशीन निर्माण उद्योग की शुरुआत होगी। मंत्रिपरिषद के इस महत्वपूर्ण निर्णय से राज्य में बड़े निवेश को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। राज्य में संयंत्र की स्थापना से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और छत्तीसगढ़

विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा। मंत्रिपरिषद् ने लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों के डिजिटल प्रबंधन के लिए वर्क्स एण्ड अकाउंट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लागू करने के प्रथम चरण को मंजूरी दी है। इस प्रणाली के माध्यम से कार्यों की स्वीकृति, ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-मेजरमेंट बुक, बिल भुगतान, लेखा प्रबंधन तथा गुणवत्ता की निगरानी जैसी सभी प्रक्रियाएं एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित होंगी। सी-डैक, पुणे द्वारा विकसित इस प्रणाली को पहले लोक निर्माण विभाग में लागू किया जाएगा, जिसके बाद अन्य निर्माण एवं अधोसंरचना विभागों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। इससे निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, भुगतान की प्रक्रिया तेज होगी, कार्यों की रियल-टाइम निगरानी संभव होगी और परियोजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनेगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत बारहमासी सड़कों के निर्माण हेतु जारी दिशा-निर्देशों में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। संशोधनों के तहत ग्रामीण आंतरिक गलियों में सीसी सड़क एवं नाली निर्माण तथा सड़क निर्माण (शेष पृष्ठ 6 पर...)

संसद का विशेष सत्र: 16 से 18 अगस्त तक हो सकती है बैठक, परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर हो सकती है चर्चा



रिज्जू की राहुल से मुलाकात; सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल राज्यसभा में पास

नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार संसद के मौजूदा विधायी कार्य को आगे बढ़ाया जाए। जैसे ही सरकार मानसून सत्र के समापन के ठीक बाद एक विशेष सत्र बुलाने की योजना पर काम कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, चल रहा मानसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त होगा, जिसके बाद 16 से 18 अगस्त तक संसद का दो-दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया जा सकता है। इस विशेष सत्र के दौरान सरकार का मुख्य एजेंडा अपने बेहद महत्वाकांक्षी परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल पर चर्चा करना और उन्हें आगे बढ़ाना है।

दो-तिहाई बहुमत जुटाने में जुटी सरकार

कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार इस संवैधानिक संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े को पूरा करने में जुटी हुई है। सरकार की यह कोशिश है कि संसद में संख्या बल पूरी तरह मजबूत होने के बाद ही इस अहम

विधेयकों को चर्चा और बाद में पारित कराने के लिए लाने से पहले, केंद्र सरकार संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने और विपक्ष के साथ आम सहमति बनाने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो गई है। इसी को देखते ही, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरन रिज्जू ने बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ करीब 50 मिनट तक लंबी बैठक की। यह मुलाकात संसद में चल रहे गतिरोध को तोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। (शेष पृष्ठ 6 पर...)

गतिरोध खत्म करने के लिए विपक्ष से संपर्क

इन दो महत्वपूर्ण विधेयकों को चर्चा और बाद में पारित कराने के लिए लाने से पहले, केंद्र सरकार संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने और विपक्ष के साथ आम सहमति बनाने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो गई है। इसी को देखते ही, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरन रिज्जू ने बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ करीब 50 मिनट तक लंबी बैठक की। यह मुलाकात संसद में चल रहे गतिरोध को तोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। (शेष पृष्ठ 6 पर...)

पीएम नरेन्द्र मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मांगी माफी, सरकार ने दिया था अल्टीमेटम

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री की पोस्ट हटाने वाले मामले में मेटा ने माफी मांग ली है। मेटा के चीफ रलोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कपलान ने कहा है कि पीएम मोदी की पोस्ट को रोकने वाली गलती के लिए मैंने मेटा की ओर से मंत्री से माफी मांगी है। मेटा के रलोबल अफेयर्स हेड जोएल कपलान के नेतृत्व में कंपनी की एक टीम ने केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इससे पहले टीम ने IT सचिव एस. कृष्णन के साथ भी बैठक की।



यह मामला तब सामने आया था जब 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फेसबुक पोस्ट कुछ समय के लिए हटा दी गई थी। इस पोस्ट में उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए पेपर लोक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया था। यह वीडियो पहले इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था और बाद में फेसबुक पर शेयर किया (शेष पृष्ठ 6 पर...)

चाहे जो हो, मैं अपने लोगों के पास वापस जाऊंगी; दो साल बाद शेख हसीना का पहला लाइव संबोधन

नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोडिया से वक्तुअल बातचीत में कहा कि मैं उस व्यक्ति के रूप में बोल रही हूँ जिसने अपना जीवन बांग्लादेश के लोगों के साथ बिताया और मुझे भरे देश से दूर कर दिया गया, लेकिन मैं अपने लोगों से कभी अलग नहीं हुई। उन्होंने दो साल पहले हुए हिंसक प्रदर्शनों की निंदा की।

मोडिया को संबोधित करते हुए शेख हसीना ने कहा कि पिछले दो सालों में मैंने अपने प्यारे बांग्लादेश को पीड़ित होते हुए देखा है। यह वह बांग्लादेश नहीं है, जिसे हमने बनाया था, यह वह बांग्लादेश नहीं है जिसके लिए 1971 में 30 लाख लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं जुलाई और अगस्त 2024 के बारे में सच्चाई बताती हूँ। यह शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन नहीं था। मेरी सरकार ने शरू से बावर्तीक, कानूनी प्रक्रिया और धैर्य के माध्यम से इस मुद्दे को शांतिपूर्वक हल करने की कोशिश की, लेकिन सुधार

की भाषा के पीछे, संगठित समूह छात्रों की मांग को हिंसक राजनैतिक हथियार में बदलने के लिए काम कर रहे थे।

सोच समझकर तैयार किया गया आंदोलन था- हसीना

उन्होंने कहा कि खुद मुहम्मद यूनस ने कहा कि यह एक सोच समझकर तैयार किया गया आंदोलन था, जिसका नेतृत्व एक मास्टरमाइंड कर रहा था। उनके अपने शब्द ही सच्चाई थे। यह महज छात्रों का स्वतः स्फूर्त विरोध-प्रदर्शन नहीं था। हसीना ने कहा कि इसका कोई साफ या जिम्मेदार नेतृत्व नहीं था, निर्देश गुप्त रूप से दिए जा रहे थे। इसे संगठित और निर्देशित किया गया था और इसका इस्तेमाल ब्लैट बविस के बाहर सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बनाने के लिए किया गया था। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने कहा कि सबसे पहले आपने 2024 के इस विरोध प्रदर्शन में (शेष पृष्ठ 6 पर...)

कानून व्यवस्था की हालत से सांसद चिंतित: बृजमोहन ने सीएम साय और गृहमंत्री शर्मा को लिखा पत्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर के साथ स्वामी विवेकानंद की कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय प्रभाषी को पत्र लिखकर पुलिस व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग की है। उन्होंने राजधानी की सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

सांसद ने अपने पत्र में रायपुर पुलिस कमिश्नरेंट और ग्रामीण पुलिस के पुनर्गठन की आवश्यकता बताते हुए शहरी क्षेत्रों

एयरपोर्ट को भी कमिश्नरेंट क्षेत्र में शामिल करने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि इससे पुलिसिंग अधिक प्रभावी होगी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। बृजमोहन अग्रवाल ने पुलिस विभाग में 660 से अधिक रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने की मांग की है। साथ ही तत्काल राहत के लिए 500 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की अस्थायी तैनाती करने का भी आग्रह किया है, ताकि बढ़ते कार्यभार और (शेष पृष्ठ 6 पर...)



पुलिस में बड़े सुधार की मांग

बिना इश्योरेंस गाड़ी को नहीं मिलेगा पेट्रोल! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सुझाव, थर्ड-पार्टी बीमा अवधि भी बढ़ाई

नई दिल्ली। यदि आपकी गाड़ी का इश्योरेंस नहीं है, तो आने वाले समय में पेट्रोल पंप पर ईंधन मिलना मुश्किल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिना बीमा वाले वाहनों पर सख्ती की जरूरत बताते हुए सुझाव दिया कि जिन वाहनों का वैध बीमा नहीं है, उन्हें पेट्रोल-डीजल न दिया जाए। साथ ही ऐसे वाहनों की पहचान कर उनके मालिकों को ई-चालान भी किया जाए।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि देश की सड़कों पर चल रहे करीब 56 प्रतिशत वाहन, जिनमें अधिकांश दोपहिया हैं, बिना बीमा के हैं। यह स्थिति मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 के उद्देश्य को ही विफल कर देती है। इससे सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा पाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। देश में 30.4 करोड़ पंजीकृत वाहनों में से करीब 16.5 करोड़ वाहन बिना बीमा के हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं के 22 प्रतिशत मामलों में बिना बीमा वाले वाहन शामिल होते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करें, जिसके तहत वाहनों को ईंधन तभी मिले, जब उनका इश्योरेंस ई-चालान भी किया जाए।

वैध है। यदि बीमा समाप्त हो चुका है तो संबंधित वाहन को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाए। पीठ के अनुसार, इस व्यवस्था से बिना बीमा और बिना पंजीकरण वाले वाहनों की पहचान आसान होगी तथा वाहन मालिक समय पर बीमा कराने के लिए प्रेरित होंगे। अदालत ने यह भी कहा कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को इस प्रस्ताव पर सिद्धांततः कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि हाइवे और प्रमुख सड़कों पर लगे कैमरों को वाहन पोर्टल और इश्योरेंस इन्फॉर्मेशन (शेष पृष्ठ 6 पर...)



छात्रों का लगातार शोषण हो रहा है, छात्र भारत के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने कोई हिंसा नहीं की - राहुल गांधी

नई दिल्ली। राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली में 10 जनपथ पर जंतर-मंतर प्रदर्शनकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा कि 20 जुलाई को हुए कांकेरोच पार्टी के प्रदर्शन के दौरान स्टूडेंट पर लाठी-पैलेट गन से हमला किया गया। राहुल अपने साथ चार प्रदर्शनकारी छात्र और छात्राओं को मोडिया के सामने लाए। एक छात्र ने कहा- भारत माता की जय बोलने पर हमें देशद्रोही कहा गया। हम शांति से चल रहे थे तो एक पुलिस अफसर ने शरीर के ऊपरी हिस्से पर मारा। राहुल गांधी ने कहा- प्रदर्शनकारियों ने कुछ भी गलत नहीं किया। इनका लगातार शोषण हो रहा है। ये बच्चे देश के भविष्य के लिए लड़ें। इन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। लोकतंत्र के लिए ये बच्चे लड़ें, इसके लिए इनका धन्यवाद।



जंतर-मंतर प्रदर्शनकारियों के साथ राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस: लड़कों ने कहा- भारत माता की जय बोलने पर देशद्रोही कहा, शांति से चलने पर भी मारा

साथ मारपीट की गई, धमकाया गया और दबाव बनाया गया। मुझे उन पर और देशभर के हजारों युवाओं पर गर्व है। उन्होंने संविधान, भारत के विचार और देश के भविष्य की रक्षा की है। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले छात्रों के घर गुंडे भेजना, 15 साल की एक लड़की से जबरन

माफी मंगवाना और फिर उस माफी को स्वीकार करना पूरी तरह बेतुका है। हम इसे स्वीकार नहीं करते। हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं जो सत्य को स्वीकार करे, परीक्षा घेप करीब रुके और देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे।

छात्रों से जबरन माफी मंगवाने की कोशिश

राहुल गांधी ने आगे कहा कि प्रदर्शन के बाद से छात्रों का लगातार मानसिक शोषण हो रहा है। राहुल ने कहा कि छात्रों ने कुछ भी गलत नहीं किया है। उनसे जबरन माफी मंगवाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आपकी माफी स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता है। छात्रों किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ भी गलत नहीं किया। राहुल ने कहा कि छात्रों ने किसी भी तरह की हिंसा नहीं की है। इन छात्रों पर दबाव बनाने के लिए उनके घर पर गुंडे भेजे जा रहे हैं। इतना ही नहीं 15 साल की बच्चियों को परेशान (शेष पृष्ठ 6 पर...)

सीएसएमसीएल घोटाला: अनवर देबर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, सुनवाई पूरी होने तक छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा

रायपुर। शराब घोटाले से जुड़े छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड घोटाला (CSML) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी अनवर देबर को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने जमानत के साथ सख्त शर्तें भी लगाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि ट्रायल के दौरान अनवर देबर छत्तीसगढ़ से बाहर रहेगा।



अधिकारियों को दोगे अपना पता-फोन नंबर

इसके साथ ही उन्हें अपने रहने का पता और मोबाइल नंबर संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराना होगा। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने की है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रायल के दौरान जब भी अदालत बुलाएगी, अनवर देबर को पेश होना होगा। सुनवाई के दौरान अनवर देबर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने पैरवी की।

हार्डकोर्ट ने पहले स्टाटिज कर दी थी जमानत याचिका

इससे पहले 13 मई को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनवर देबर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पहली नजर में रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से राज्य सरकार के निगम में गहराई तक फैले एक संगठित भ्रष्टाचार तंत्र का संकेत मिलता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि सार्वजनिक धन से जुड़े आर्थिक अपराध सामान्य अपराधों की तुलना में अधिक गंभीर होते हैं। ऐसे मामलों में बड़े पैमाने पर जनता के पैसे के नुकसान और सुनिश्चिंत साजिश की आशंका रहती है, जिसका असर व्यापक स्तर पर पड़ता है। इसलिए ऐसे मामलों में जमानत पर विचार करते समय विशेष सावधानी बरतना जरूरी है। यह मामला आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और भ्रष्टाचार (शेष पृष्ठ 6 पर...)

10 करोड़ नशामुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान का भव्य शुभारंभ : विकसित भारत की दिशा में सशक्त पहल

ब्रह्माकुमारीज के ज्ञान मानसरोवर परिसर में हुआ आयोजन, 6 से 20 अगस्त तक चलेगा देशव्यापी अभियान

राजनांदगांव (दावा)। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एवं भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित देशव्यापी '10 करोड़ नशामुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान' का भव्य शुभारंभ 4 अगस्त को ब्रह्माकुमारीज के ज्ञान मानसरोवर परिसर में संपन्न हुआ। यह महाअभियान 6 अगस्त से 20 अगस्त तक पूरे देश में संचालित किया जाएगा। जिसके तहत 10 करोड़ नागरिकों को नशामुक्ति की शपथ दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान ब्रह्माकुमारीज की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की 19वीं पुण्य स्मृति को समर्पित है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मुख्य जिला



चिकित्सा अधिकारी डॉ. एन.आर. नवरतन, नशा मुक्ति केंद्र की नोडल अधिकारी डॉ. निहारिका, डॉ. विकास, विशिष्ट अतिथि राजयोगी भारत भूषण, पीयूष एवं सेवाकेंद्र संचालिका ब्रह्माकुमारी पुष्पा बहन द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। अतिथियों ने नशामुक्त समाज के निर्माण पर जोर देते हुए कहा कि युवाओं को नशे की

लात से बचना आज की सबसे बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है। वक्ताओं ने कहा कि नशामुक्ति केवल व्यक्तिगत संकल्प नहीं, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य का आधार है। स्वस्थ और जागरूक नागरिक ही विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। अभियान के तहत 6 से 20 अगस्त तक देशभर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, प्रतिज्ञा समारोह, रैलियां एवं जनसंपर्क अभियान आयोजित किए जाएंगे। आयोजकों ने आम जनता से इस महाअभियान से जुड़कर नशामुक्त और स्वस्थ भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। कार्यक्रम का कुशल संचालन ब्रह्माकुमारी प्रभा बहन द्वारा किया गया।

गर्व की बात : रॉयल किड्स कान्टेंट के लव्यांश ने इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में मारी बाजी



राजनांदगांव (दावा)। रॉयल किड्स कान्टेंट के होनहार छात्र लव्यांश लहरी (पिता किशोर लहरी, माता अंजलि लहरी) ने कोलकाता में आयोजित इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और कांस्य पदक पर कब्जा जमाया है। रियो दो संगठन द्वारा

हॉशी प्रेमिथ सेन के नेतृत्व में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में नौ देशों के सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। लव्यांश ने प्रतियोगिता में कुल 4 राउंड खेलते हुए सभी प्रतिद्वंद्वियों को पछड़कर फाइट कैटेगरी में स्वर्ण पदक और काता कैटेगरी में कांस्य पदक अपने नाम किया।

कोलकाता में आयोजित प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण और कांस्य पदक

लव्यांश की इस उपलब्धि पर शाला परिवार में हर्ष का माहौल है। इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष डॉ. सविता जेबी सिंह, उपाध्यक्ष अशोक चौधरी, प्रशासक संजय बहादुर सिंह, बोर्ड मेंबर टी.एस. बग्गा, सावंत बहादुर सिंह, जन्मेजय बहादुर सिंह, श्रेयांश बहादुर सिंह, मनीषा सिंह, पूजा सिंह, जानवी सिंह, ईला सिंह, बंसर आई.के. वैष्णव, एकेडमिक डायरेक्टर अभिषेक खंडेलवाल, प्राचार्या एकता खंडेलवाल, ममता मिश्रा, सरिता सिंह, अपर्णा वर्मा एवं समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं ने लव्यांश को उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद व बधाई दी।

पहला कॉलम...

किसानों के पंजीयन में रोड़ा और परिवार में बखेड़ा : कांग्रेस परिवार को तोड़ने की साजिश कर रही सरकार : रूपेश



राजनांदगांव (दावा)। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रूपेश दुबे ने राज्य की भाजपा सरकार पर धान खरीदी की जिम्मेदारी से बचने के लिए किसानों पर नए-नए नियम थोपने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एपी स्टैक पंजीयन के नाम पर किसान परिवारों में बंटवारा और विघटन कराने की साजिश रची जा रही है। जो कृषक परिवारों के साथ करुणा का प्रमाण है। प्रदेश प्रवक्ता रूपेश दुबे ने बताया कि एपी स्टैक पोर्टल में पंजीयन के लिए शामिलता (संयुक्त) खाते वाले किसान परिवारों के सभी सदस्यों की उपस्थिति और पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार आज तक इस पोर्टल के सर्वर को दुरुस्त नहीं कर सकी है। जिसके कारण बीते वर्ष भी लगभग 2 लाख किसान धान बेचने से वंचित रह गए थे। उन्होंने कहा कि संयुक्त खाते के सभी सदस्यों का पंजीयन अनिवार्य होने से परिवार के वे सदस्य (बहन, बेटी या भाई) जो विवाह या रोजगार के सिलसिले में अन्य जिलों या राज्यों में रहते हैं। उन्हें काम छोड़कर आना पड़ रहा है। सर्वर डाउन रहने के कारण उन्हें दो-तीन दिनों तक भटकना पड़ता है। जिससे उनके रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और परिवारों में दार व बंटवारे के हालात बन रहे हैं। रूपेश दुबे ने आरोप लगाया कि धान खरीदी से बचने के लिए सरकार यह साजिश रच रही है।

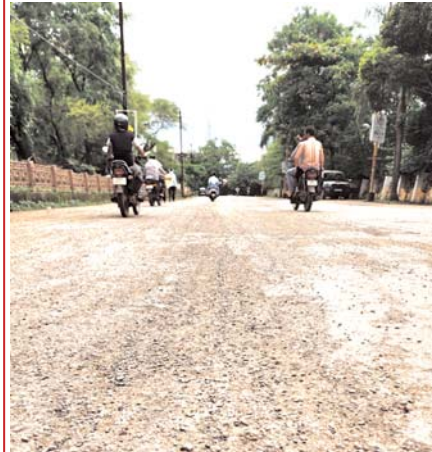
आयुष पॉलीक्लीनिक में पौधरोपण संपन्न



राजनांदगांव (दावा)। महापौर मधुसूदन यादव आयुष पॉलीक्लीनिक दीनदयाल नगर चिखली राजनांदगांव परिसर में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में एक पेड़ माँ के नाम एवं जहां हरियाली वहां खुशहाली का संदेश देते हुए बड़ी संख्या में पौधरोपण किया गया। महापौर ने पौधरोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा नागरिकों को पर्यावरण व स्वास्थ्य संरक्षण के लिए पौधरोपण करने प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त जीआर मरकाम ने प्रधानमंत्री सूर्यचर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी तथा जनमानस को योजना का लाभ लेने तथा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में नीम, कचनार, तुलसी, अमलतास, आंवला, कदम, अर्जुन, रीठा, हरी, मुन्गा, बहेड़ा, शिकारदाई, अक्षगंधा, जामुन, पलाश, बेल सहित अन्य औषधी वनस्पति, फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण किया गया।

बारिश ने खोली निर्माण कार्यों की पोल : शहर की सड़कों की दुर्गति, आवाजाही में लोग परेशान

जगह-जगह पर उभरे जानलेवा गड्ढे और जलजमाव, घटिया निर्माण के चलते पहली ही बारिश में उखड़ी लाखों की सड़कें



राजनांदगांव (दावा)। जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही रुक-रुक कर और तेज बारिश ने शहर की सड़कों के दावों की पूरी पोल खोलकर रख दी है। शहर की लगभग हर मुख्य सड़क बारिश के पानी से उधड़ चुकी है। बारिश की बूंदों से डामर उखड़ गया है और सड़कों पर नुकीली गिट्टियां फैल गई हैं, जिससे पैदल

चलने वाले राहगीरों के पैरों में छालें पड़ रहे हैं। वहीं वाहन चालकों को छलनी हो चुकी सड़कों, गहरे गड्ढों और दरारों के बीच से जोखिम भरा सफर तय करना पड़ रहा है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।

प्रमुख समस्याएं एवं प्रभावित इलाके

नगर निगम के पास महावीर

संस्कारधानी के कराटे खिलाड़ियों ने देश के लिए जीता 2 स्वर्ण, 1 रजत एवं 8 कांस्य पदक, महापौर ने विजेता खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह

राजनांदगांव (दावा)। इंडियन चैलेंजर्स कप अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 2026 में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम में राजनांदगांव के खिलाड़ियों ने देश के लिए 2 स्वर्ण, 1 रजत एवं 8 कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक जीतकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता के बाद विजेता खिलाड़ियों ने वरिष्ठ कराटे प्रशिक्षक सेंसई कमल पूजन के नेतृत्व में मोतीपुर स्थित महापौर निवास पहुंचकर महापौर मधुसूदन यादव से सौजन्य मुलाकात की और अपनी उपलब्धियों से अलगत कराया।

वरिष्ठ कराटे प्रशिक्षक कमल पूजन ने महापौर को बताया कि शोईशिनकाई शितोरियू



कराटे डू फेडरेशन एवं कराटे डू एसोसिएशन बंगाल के संयुक्त तत्वावधान में नेताजी इंडोर स्टेडियम, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें टीम कोच सेंसई शशांक गुप्ता (छत्तीसगढ़ राज्य प्रमुख) के नेतृत्व में राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर एवं रायपुर के खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रतियोगिता में 9 देशों के 8,900 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था।

राजनांदगांव जिले के पदक विजेता खिलाड़ियों में काजल यादव : स्वर्ण पदक (काता-कुमिटे फाइट), लव्यांश लहरी : 1

स्वर्ण एवं 1 कांस्य पदक (काता-कुमिटे), कैटरियल दान : 1 रजत एवं 1 कांस्य पदक (काता-कुमिटे), आदित्य राज देवांगन : 1 कांस्य पदक (काता), अरुण साहू : 2 कांस्य पदक (काता-कुमिटे), थलेश्वरी मेथ्राम : 1 कांस्य पदक (कुमिटे) व पलक नेमा 2 कांस्य पदक (काता-कुमिटे) आदि है। ये सभी खिलाड़ी स्थानीय तुलसीपुर में सेंसई कमल पूजन से निरंतर कराटे का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। महापौर मधुसूदन यादव ने सभी विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनकर बधाई दी और उन्हें भविष्य में भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश व प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया।

गुजराती स्कूल के दो विद्यार्थियों का संभाग स्तरीय कराटे प्रतियोगिता के लिए चयन, विद्यालय में खुशी की लहर

रियांस साहू और नवाज खान 10 अगस्त को भिलाई में दिखाएंगे अपना दम

राजनांदगांव (दावा)। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आयोजित जिला स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के अंतर्गत कस्तूरबा स्कूलों में कराटे स्पर्धा का आयोजन किया गया। इसमें गुजराती राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक शाला के दो होनहार विद्यार्थियों- कक्षा 10वीं के छात्र रियांस साहू (अंडर-19) और कक्षा



8वीं के छात्र नवाज खान (अंडर-17) का चयन संभाग स्तरीय कराटे

प्रतियोगिता के लिए हुआ है। दोनों चयनित खिलाड़ी 10 अगस्त को भिलाई के लिए रवाना होंगे।

इस उपलब्धि पर विद्यालय परिवार, अभिभावकों और विद्यार्थियों में भारी उत्साह है। प्राचार्या श्रीमती सुष्मा शुक्ला ने चयनित खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि अनुशासन, समर्पण और निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों विद्यार्थी संभाग स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करेंगे। उपप्राचार्या श्रीमती अर्पणा श्रीवास्तव ने

कहा कि खेल व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास का सबसे बड़ा माध्यम है। कराटे प्रशिक्षक सुधा साहू एवं अनुसुइया साहू ने बताया कि खिलाड़ियों ने कठिन परिश्रम से यह मुकाम हासिल किया है। संस्था के अध्यक्ष विनय पटेल, उपाध्यक्ष पवन पटेल, सचिव सीए रूपम सोनखत्रा, कोषाध्यक्ष हिमांशु पटेल, निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों विद्यार्थी संभाग स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करेंगे। उपप्राचार्या श्रीमती अर्पणा श्रीवास्तव ने

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में टीईटी परीक्षा आयोजित करें राज्य सरकार : राजेश चटर्जी

लाखों शिक्षकों एवं उनके परिवारों में भविष्य को लेकर उपजी चिंता का समाधान करे सरकार : शिक्षक फेडरेशन

राजनांदगांव (दावा)। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांतध्यक्ष राजेश चटर्जी, प्रांतीय प्रमुख महामंत्री सतीश ब्यूहरे, जिलाध्यक्ष पी.आर. झाड़े सहित पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न होने की स्थिति में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका (सिविल) 1385/2025 के आदेश (29 मई 2026) के पैरा-34 में राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सभी राज्य सरकारों के सक्षम प्राधिकारी ज़रूरत परीक्षा नियमित रूप से, अधिमानतः वर्ष में दो बार (छह महीने के अंतराल में) आयोजित करें, ताकि कार्यरत शिक्षकों को उचित अवसर मिल सके। सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यरत शिक्षकों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक का समय निर्धारित किया है। इसके पूर्व पारित आदेश के अनुसार, जिनकी सेवा 5 साल से कम बची है। वे सेवानिवृत्ति तक पद पर बने रहेंगे किंतु पदोन्नति के दायरे में नहीं आएंगे। वहीं पदोन्नति के आकांक्षी शिक्षकों के लिए टेट अर्हता अनिवार्य होगी। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में टेट परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक



परीक्षा मंडल की है। एनसीटीई के 23 अगस्त 2010 के राजपत्र से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए ज़रूरत अनिवार्य नहीं था और छत्तीसगढ़ में भर्ती नियमों या नियुक्ति पत्रों में भी इसका उल्लेख नहीं था। ऐसे में यदि राज्य सरकार परीक्षा ही आयोजित नहीं करेगी तो शिक्षक इसमें सम्मिलित कैसे होंगे? फेडरेशन ने मांग की है कि छत्तीसगढ़ शासन भी उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की तर्ज पर कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष विभागीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) आयोजित करे, ताकि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षक 31 अगस्त 2028 की समय-सीमा के भीतर वैधानिक आवश्यकता को पूर्ण कर

सकें और अवसरों के अभाव में किसी का भविष्य संकट में न पड़े।

फेडरेशन की शासन से अपील

शिक्षकों के सम्मान, आजीविका और भविष्य की रक्षा के लिए फेडरेशन ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव एवं व्यापक सचिव से सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार राज्य में समयबद्ध तरीके से टेट आयोजित करने का आग्रह किया है। साथ ही प्रभावित शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण, अध्ययन सामग्री और परीक्षा की तैयारी हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी निवेदन किया है।

वर्देमातरम् 150वीं वर्षगांठ पर 7 से 15 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन

राजनांदगांव (दावा)। वर्दे मातरम् 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर तृतीय चरण 7 से 15 अगस्त (हर घर तिरंगा के साथ) जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, ग्राम पंचायत, विद्यालय, महाविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। हर घर तिरंगा के साथ तिरंगा यात्रा, मशाल रैली एवं देशभक्ति गीत प्रतियोगिता, विचार गोष्ठी, संगोष्ठी एवं छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुरूप राज्य क्षेत्र के सभी स्कूलों के बेंड द्वारा वर्दे मातरम् से संबंधित संगीतमय कार्यक्रम विद्यालय एवं महाविद्यालय में आयोजित की जाएंगी। जिसमें एनसीसी, एनएसएस, स्काउट-गाइड की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

